Threats faced by journalists in rural and other areas

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, आज मैं आपके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले पत्रकारों के सामने आने वाली तमाम जोखिम भरी चुनौतियों की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, आज समाज के बदलते परिवेश में पत्रकार चाहे प्रिंट मीडिया में हों अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हों, उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पत्रकार समाज के दबे, कुचले, उपेक्षित, शोषित, उत्पीड़ित, अपमानित व बेज़ुबान लोगों को ज़ुबान देने का काम करता है। वह समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा समाजद्रोही तत्वों की कारगुज़ारी उजागर करके अनेक प्रकार के खतरों से खेलता है। बहुत बार वह अपने प्राणों को भी संकट में डालता है। मान्यवर, आज पत्रकार की लेखनी और उसका चिंतन स्वतंत्र नहीं रह गया है। उसको अपने मालिकान और संपादक के इशारे पर न चाहते हुए भी अपनी लेखनी को चलाना पड़ता है। मान्यवर, पत्रकारिता एकमात्र सशक्त माध्यम है। लोकतंत्र के जो तीन स्तंभ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका हैं, वह उन पर निगरानी रखने में अपनी अहम भूमिका अदा करती है। पत्रकारिता, दुरूह क्षेत्र में महानगरों की सीमाओं तक नहीं, सुदूर गांवों, कस्बों तथा शहरों तक पहुंची हुई है।

मान्यवर, आए दिन पत्रकारों की हत्या, उन पर होने वाले हमले और उत्पीड़न की धमकियों के बारे में समाचार मिलते रहते हैं। उसके बाद भी वे अपनी जान जोखिम में डालकर अपना दायित्व पूर्ण करते हैं। सर, ऐसे में पत्रकारों के सामने आने वाली समस्याओं का चिंतन और उनकी समस्याओं का निदान करना अति आवश्यक हो गया है। इसके लिए मैं आपके और सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पत्रकारों की गर्दन पर जो संपादकों व मालिकान की एक तलवार लटकती रहती है कि पता नहीं उन्हें वे कब निकाल दें, इसके लिए ग्रामीण कस्बों, छोटे-बड़े शहरों में कार्य करने वाले सभी पत्रकारों को सेवा-सुरक्षा की नियमावली का मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए।

मान्यवर, दूसरे 80 प्रतिशत पत्रकार ऐसे हैं, जो 10-12 हज़ार रुपये के वेतन पर कार्य करने के लिए विवश होते हैं। वे अपने दायित्व को ईमानदारी से और बिना किसी अनुचित दबाव के निर्वहन कर सकें, इसके लिए उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान सभी वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण प्रामाणिकता व बिना किसी दबाव के निर्वहन कर सकें, धन्यवाद।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

Need to grant Scheduled Tribe status to 11 Gorkha communities

श्रीमती शांता क्षत्री (पश्चिम बंगाल): धन्यवाद सर, मैं आपके माध्यम से माननीय ट्राइबल मिनिस्टर का ध्यान अपनी बात पर आकर्षित करना चाहती हूं। सर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बहुत सारी हिल ट्राइबल्स communities हैं और साथ में सिक्किम में भी Tribal Communities हैं। दार्जिलिंग में हम लोगों की जो 11 Tribal Communities हैं, पश्चिम बंगाल सरकार की माननीय मुख्य मंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने वर्ष 2014 में इन 11 communities को ट्राइबल स्टेटस देने के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमंडेशन भेजी थी। मान्यवर, अभी तक 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन 11 communities को ट्राइबल स्टेटस नहीं मिला है। वर्ष 2014 में जब लोक सभा इलेक्शन हुए थे। ...**(व्यवधान)**...